हो रहा है। इस परिस्थिति में आम जनता बराबर धरना, प्रदर्शन एवं अनशन के द्वारा केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित कर रही है।

बिहार के मुख्यमंत्री ने 26 जुलाई को विधान सभा में विधायकों के समक्ष कहा कि दामोदर घाटी निगम के अधिकारियों से कहकर मुख्यालय बिहार के माईथाण, हजारी बाग या रांची में लाने के लिए कहा गया है। बिहार सरकार उपेक्षित जमीन मुख्यालय हेतु अर्जित करने के लिए तैयार है। अतः भारत सरकार से अपील है कि दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय बिहार में लाकर जनता को उचित न्याय दिलाया जाये। यह जनहित के लिए एक अनिवार्य कदम होगा। (इति)

12.28 Hrs.

ELECTRICITY (SUPPLY) AMENDMENT BILL—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER : Hon. Members, we shall now take up the Legislative Business—the Electricity (Supply) Amendment Bill.

The time allotted for the Electricity (Supply) Amendment Bill is 4 hours. We have already exhausted 4 hours and 16 minutes. But I would like to give chance to all Members who want to speak. I do not want to stop any Members, let him speak. But I would ask the Members to be as brief as possible because we have already exhsuated the time.

SHRI CHITTA BASU : A good gesture, Sir.

SHRI GEORGE FERNANDES : Sometimes you are a good Deputy-Speaker.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I hope I shall always be.

Now, Mr. Ashfaq Hussain has to continue his speech. But he is absent. So, now Mr. Namgyal may speak.

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : उपाध्यक्ष महोदय, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 1983 पर बहस चल रही है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। इस बिल में इसके तरमीम का मकसद बताया गया है और माननीय मंत्री जी ने भी अपने भाषण में इसकी तरमीम करने का मकसद भी बताया है। स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड जितनी सरप्लस रेवेन्यू कमाएंगे वह एकाउंट में दिखाएंगे। लेकिन इसका Quantum of Surplus किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने सरप्लस रेवेन्यू में नहीं दिखाई है। इस वजह से इन बोर्डों का आपस में वर्किंग कंपेरीजन करने में मुश्किल होती है। इस बिल में कोई भी इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड तीन परसेंट से ज्यादा रेवेन्यू कमाएंगे तो उसको स्पेसिफाई करना आपने लाजिमी करार दिया है। कमर्शियल एकाउंटिग का जो तरीकेकार है उन्हीं लाइंज पर बोर्डों के एकाउंट्स को लाना आपने इस बिल में लाजिमी करार दिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कुछ रूल्ज बनाने के अखत्यारात देने की बात कही है।

जहां तक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्डज की कारकर्दगी का सवाल है, अखबारों में आपको हर रोज पढ़ने को मिलेगा कि हर स्टेट में कहीं न कहीं पावर शैडिंग हुई है। मतलब यह कि इन बोर्ड्ज का जो वर्किंग है वह तसल्लीबख्श नहीं है। परसों की बात है। एक सवाल के जवाब में आपने कहा था कि नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन से इस कद्र बिजली ली गई है कि सात स्टेट्स के ऊपर कुल मिला कर तीन सौ करोड़ का बकाया है। इसके इलावा एक स्टेट दूसरी स्टेट से जो भी लेती है। वह अलग है जैसे जम्मू कश्मीर स्टेट पंजाब और हिमाचल से बिजली लेती है। वह इस में दिखाई नहीं गई है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बोर्ड्ज का जो वर्किंग है वह तसल्लीबख्श नहीं है।

आपने इस बिल में तीन परसेंट सरपलस अगर रेवेन्यू होता है तो उसको दिखाना, उसको स्पेसिफाई करना लाजिमी करार दिया है। एक चीज मेरी समझ में नहीं आई। जैसे दूसरे मेंबर साहिबान ने भी प्वाइंट आउट किया कि तीन परसेंट से ज्यादा स्पेसिफाई करने का सवाल ही कहां पैदा होता है जब सारे बिजली बोर्ड घाटे में चल रहे हैं। मैं मिनिस्टर साहब का मशकूर

हूंगा अगर वह इसको हमें समझा दें ।

जहां तक बिजली सप्लाई और जैनरेशन का सवाल है एक बात जानना जरूरी है। हमारे मुल्क में टोटल इंस्टाल्ड कैपेसेटी कितनी है और उस में से है एक्चुअली कितना जैनरेशन हो रहा है और युटिलाइजेशन उस में से कितना हो रहा है। अगर ये फिगर्ज हमें बताए जाएं तो हम जान सकेंगे कि बिजली बोर्डज का वर्किंग सही ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है। मेरे ख्याल में नहीं चल रहा है। हर जगह बिजली का मसला है। साथ ही लीकेजिज या या लासिस भी हैं। और भी बहुत से माननीय सदस्यों ने दोनों तरफ से कहा है कि लीकेज बहुत है, ट्रांसमिशन लासिस हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा हैं।

जहां तक लीकेजेज का सवाल है वह हमारे देश में सबसे ज्यादा है। सबजेक्ट टू करेक्शन नेशनल ऐवरेज लीकेजेज का देश में 21 परसेंट से ज्यादा है, और जम्मू कश्मीर में लीकेज 41 से 45 परसेंट है। और कश्मीर बैली में तो, अगर मैं गलती नहीं करता, 60 परसेंट तक लीकेज है। दुनियां का रेकार्ड बीट कर गया है। इन लीकेजेज को कैसे प्लग करना है, यह आपको सोचना चाहिये। बिजली की लीकेजेज बिजली दफ्तर के कर्मचारी और कंज्यूमर की मिली भगत से ही हो रहे हैं। हमने देखा है हर महीने मीटर रीडिंग करने वाला आता है उसके जाते ही दूसरा कर्मचारी सीढ़ी ले कर जाता है, पहले डायरेक्ट कनेक्शन लगा कर जाता है, उनको पता होता है कि कल रीडिंग होने वाली है तो एक दिन पहले आता है सही ढंग से कनैक्शन करके जाता है और रीडिंग लेने वाला आकर रीडिंग ले जाता है। इसके बाद फिर दूसरे कर्मचारी आयेंगे, तो उसका कनेक्शन फिर डायरेक्ट कर के जाता है। लेकिन वाकया यह है कि 24 घंटे का कनेक्शन जाहिरा तौर पर ही होता है, बाकी दिन बिजली मुफ्त में जलाते हैं कर्मचारियों की मिली भगत से और इस तरह काफी नुकसान हो रहा है। अत: आपको बिजली लीकेज को ठीक ढंग से चैक करना चाहिये ताकि रोजाना जो लोड शैडिंग होती है वह दूर हो।

हमारे जम्मू-कश्मीर में यह प्रोबलम रोजाना देखने में आती है क्योंकि हमारे वहां गर्मियों में तो काफी जैनरेशन होता है, लेकिन जाड़े में पानी कम होने की वजह से जैनरेशन कम हो जाता है और नार्दर्न ग्रिड से तसल्लीबख्श बिजली नहीं मिलती है। और लोग भी जाड़े में हीटर वगैरह ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इसलिए बिजली की चोरी करते हैं। और इस तरह लीकेजेज होने की वजह से लोड काफी बढ़ जाता है और शैडिंग हो जाता है। इस पर आपको तवज्जह देनी चाहिये।

सैंट्रल गवर्नमेंट के दो प्रोजेक्टस जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, सलाल प्रोजेक्ट और दूल हस्ती प्रोजेक्ट। सलाल प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट को काम ठीक ढंग से करने नहीं दिया जाता है। स्टेट की रूलिंग पार्टी की तरफ से पालिटिकल इंटरफीयरेंस हमारे यहां काफी होता है जिसकी वजह से मैनेजमेंट ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। वहां के लेबर को इंस्टीगेट कर के काम में रुकावट डाली जाती है। अगर सलाल प्रोजेक्ट का काम ठीक से चले और समय पर पूरा हो तो मुल्क के उत्तरी भाग को काफी लाभ हो सकता है। आपको इसके मुताल्लिक हमारे राज्य के मुख्य मंत्री और बिजली मंत्री से बात करनी चाहिये कि इस तरह की रोजाना प्रोबलम्स वहां पैदा न हों ताकि वह प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी तैयार हो जाय।

इसी तरह मेरी स्टेट में जो स्टेट सैक्टर के छोटे प्रोजेक्ट हैं, खासकर मेरी कांस्टीट्एन्सी में पिछले 20 साल से कोई 2 मेगावाट कैपेसिटी का एक प्रोजेक्ट स्तकना हाइडल प्रोजेक्ट के नाम से चल रहा है, यह 3, साढ़े 3 करोड़ का प्रोजेक्ट पहले था, अब वह 17, 18 करोड़ तक पहुंच गया है और इससे सिर्फ 2 मेगावाट बिजली आने वाली है, वह भी अभी तक कम्पलीट नहीं कर सके।

इसी तरह कारगिल में माइक्रो हाइडल 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट पिछले कई साल से चल रहा है। हमारे लद्दाख सैक्टर में बिजली के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, उनकी वर्किंग बिल्कुल तसल्लीबख्श नहीं है। करप्शन हद से ज्यादा बढ़ गया है, प्राइसेस हर साल बढ़ते जा रहे हैं। आप पैसे का एलाटमेंट कम देते हैं इसीलिये 20 साल से भी अधिक में 2 मेगावाट का प्रोजेक्ट कम्पलीट नहीं हो पा रहा है। केन्द्रीय सरकार को इसे देखने की जरूरत है, इसको ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए। मेरी यही गुजारिश है कि आप कोई ऐसी रकम एक या दो साल के लिये रिलीज कर दीजिये जिससे यह बन जाये। यह नहीं कि थोड़ी-थोड़ी रकम आप देते रहें, इस तरह से नैक्स्ट ईअर फिर प्राइसेज बढ़ जाते हैं। इसीलिये यह कम्पलीट नहीं हो पा रहा है।

बिजली सप्लाई के मसले में दो एक सुझाव मैं देना चाहता हूं। जितने भी हमारे सुपरथर्मल पावर स्टेशन हैं या सुपर हाइडल या अटोमिक अनर्जी के जितने बड़े-बड़े पावर स्टेशन्ज हैं उनकी जेनरेशन और वर्किंग को केन्द्रीय सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए और जितने भी स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं उनको आपको पावर सेल करनी चाहिये। यह नहीं कि हर स्टेट अपने पावर प्रोजेक्ट को पकड़कर बैठे रहें। उनकी वर्किंग भी ठीक नहीं है, कोई सिस्टम काम करने का नहीं है। इसकी वजह से सारे मुल्क में मुश्किलात आ रही हैं। क्योंकि नार्दन ग्रिड अलग है, वैस्टर्न ग्रिड अलग है और साउदर्न ग्रिड अलग है। इसमें आप अच्छी तरह से यूनिफार्मली बिजली सेल कर पाएंगे। जो डेफिशियेंट स्टेट हैं, जहां जैनरेशन की कैपिसिटी नहीं है, चाहे हाइडल हो, थर्मल हो या दूसरे हों तो इस तरह से हरेक को यूनिफार्मली पावर मिल जायेगी।

लीकेज (Leakages) और ट्रांसमीशन लास हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा है, इसको बन्द करने के लिए भी सोचना चाहिये कि किस तरह से कम हो सकता है। ट्रांसमीशन लास के बारे में रिसर्च कर के देखना चाहिये कि इसमें कम से-कम लास हो। हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, ट्रांसमीशन लाइन को मुल्क के कोने-कोने में ले जाना पड़ता है जिसमें कई जगह ज्यादा लास हो जाता है। लीकेज के मसले में भी देखना चाहिये।

बिजली के बहुत सारी जगह मीटर हैं, मीटर में भी आपने मिनिमम चार्जेज रखे होते हैं और कई जगह फ्लेट रेट भी हैं। आप फ्लेट रेट से पैसा ले लेते हैं लेकिन बिजली वह यूज करते जा रहे हैं, उसको कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन मीटर में भी सिस्टम को देखने की जरूरत है। मिनिमम रेट आप चार्ज करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा फ्लेट दो-तीन महीने इंटर-सैशन में बन्द करके हम चले जाते हैं, लेकिन मिनिमम चार्जेज तो देना ही है, इसलिए हम सोचते हैं कि चलो, एक बत्ती जलाकर चले जाओ, इससे फर्क क्या पड़ता है, minimum तो देना ही है।

अगर कनज्यूमर्ज से मिनिमम चार्जिज के बजाए एक्चुअल रीडिंग के हिसाब से चार्ज किया जाए, तो लोग कोशिश करेंगे कि बिजली की कनजम्प्शन कम से कम रखी जाए। आज हालत यह है कि लोग एक बत्ती को चौबीस घंटे जला कर रखते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उसकी लागत मिनिमम चार्जिज से ज्यादा नहीं होगी। मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय मेरे सुझावों पर विचार करेंगे। इससे पावर में सेविंग होगी।

मन्त्री महोदय जो एमेंडमेंट लाए हैं, मैं उनकी ताईद करता हूं।

شری پھُنام گیال (لدّاخ) : اپادھیکش مہودے الیکٹری سٹی ایمینڈمینٹ بل ۱۹۸۳ء پر بحث چل رہی ہے ۔ میں اس بل کا سمرتھن کرتا ہوں ۔ اس بل میں اس کی ترمیم کا مقصد

بتایا گیا ہے اور مانیئے منتری جی نے بھی اپنے بھاشن میں اس کی ترمیم کرنے کا مقصد بتایا ہے ۔ اسٹیٹ الیکٹری سٹی بورڈ جتنی سرپلس ریوینیو کمائیں گے وہ اکاؤنٹ میں دکھائیں گے ۔ لیکن اس کا Quantum of surplus کسی بھی اسٹیٹ گورنمنٹ نے سرپلس ریوینیو میں نہیں دکھائی ہے ۔ اس وجہ سے ان بورڈوں کا آپس میں ورکنگ کمپیریزن کرنے میں مشکل ہوتی ہے ۔

اس بل میں کوئی بھی الیکٹری سٹی بورڈ تین پرسینٹ سے زیادہ ریوینیو کمائیں گے تو اس کو اسپیسی فائی کرنا آپ نے لازم قرار دیا ہے ۔ کمرشیل اکاؤنٹنگ کا جو طریقہ کار ہے انہیں لائنز پر بورڈ کے اکاؤنٹس کو لانا اپنے اس بل میں لازم قرار دیا ہے اور سنٹرل گورنمنٹ کو بھی کچھ رولز بنانے کے اختیارات دینے کی بات کہی ہے ۔

جہاں تک اسٹیٹ الیکٹری سٹی بورڈز کی کارکردگی کا سوال ہے اخباروں میں آپ کو ہر روز پڑھنے کو ملے گا کہ ہر اسٹیٹ میں کہیں نہ کہیں پاور شیڈنگ ہوتی ہے ۔ مطلب یہ ہے کہ ان بورڈز کا جو ورکنگ ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے ۔ پرسوں کی بات ہے ایک سوال کے جواب میں آپ نے کہا تھا کہ نیشنل تھرمل پاور کارپوریشن سے اس قدر بجلی لی گئی ہے کہ سات اسٹیٹس کے اوپر کل ملا کر تین سو کروڑ کا بقایا ہے ۔ اس کے علاوہ ایک اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ سے جو بجلی لیتی ہے وہ الگ ہے جیسے جموں کشمیر اسٹیٹ پنجاب اور ہماچل سے بجلی لیتی ہے ۔ وہ اس میں نہیں دکھائی گئی ہے ۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بورڈز کا جو ورکنگ ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے ۔

آپ نے اس بل میں تین پرسینٹ سرپلس اگر ریوینیو ہوتا ہے تو اس کو دکھانا اسکو اسپیسی فائی کرنا لازمی قرار دیا ہے ۔ ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آتی جیسے دوسرے ممبر صاحبان نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ تین پرسینٹ سے زیادہ اسپیسی فائی کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے جب سارے بجلی بورڈ گھاٹے میں چل رہے ہیں ۔ میں منسٹر صاحب کا مشکور رہوں گا اگر وہ اس کو ہمیں سمجھا دیں ۔

جہاں تک بجلی سپلائی اور جینریشن کا سوال ہے ایک بات جاننا ضروری ہے ۔ ہمارے ملک میں ٹوٹل انسٹال کیپیسٹی کتنی ہے اور اس میں سے ایکچولی کتنا جینریشن ہو رہا ہے اور یوٹی لائیزیشن اس میں سے کتنا ہو رہا ہے ۔ اگر یہ فیگرس ہمیں بتائے جائیں تو ہم جان سکیں گے کہ بجلی بورڈ کا ورکنگ صحیح ڈھنگ سے چل رہا ہے ۔ میرے خیال میں نہیں چل رہا ہے ۔ ہر جگہ بجلی کا مسئلہ ہے ۔ ساتھ ہی لیکیج یا لاسس بھی ہے ۔ اور بھی بہت سے مانیئے سدس نے دونوں طرف سے کہا ہے کہ لیکیج بہت ہے ۔ ٹرانسمیشن لاسس

ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے۔

جہاں تک لیکیج اور لاسس کا سوال ہے وہ ہمارے دیش میں سب سے زیادہ ہے۔ سبجیکٹ ٹو کریکشن نیشنل ایوریج لیکیجز کا دیش میں ۲۱ پرسینٹ سے زیادہ ہے اور جموں کشمیر میں لیکیج ۴۱ سے ۴۳ پرسینٹ ہے اور کشمیر ویلی میں تو اگر میں غلطی نہیں کرتا تو ۶۰ پرسینٹ تک لیکیج ہے۔ دنیا کا ریکارڈ بیٹ کر گیا ہے لیکیجز کو کیسے پلگ کرنا ہے۔ یہ آپ کو سوچنا چاہئیے۔ بجلی کی لیکیجز بجلی دفتر کے کرمچاری اور کنزیومر کی ملی بھگت سے ہی ہو رہی ہے۔

ہم نے دیکھا ہے کہ ہر مہینے میٹر ریڈنگ کرنے والا آتا ہے اس کے جاتے ہی دوسرا کرمچاری سیڑھی لے کر آتا ہے۔ پہلے ڈائریکٹ کنیکشن لگا کر جاتا ہے۔ ان کو پتا ہوتا ہے کہ کل ریڈنگ ہونے والی ہے تو ایک دن پہلے آتا ہے صحیح ڈھنگ سے کنکشن کر کے جاتا ہے اور ریڈنگ لینے والا آکر ریڈنگ لے جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے کرمچاری آئیں گے تو اس کا کنیکشن پھر ڈائریکٹ کر کے جاتا ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ۲۴ گھنٹے کا کنکشن ظاہرہ طور پہ ہی ہوتا ہے۔ باقی دن بجلی مفت میں جلاتے ہیں۔ کرمچاریوں کی ملی بھگت سے اور اس طرح کافی نقصان ہو رہا ہے۔ بلاشبہ آپ کو بجلی لاسسز کو ٹھیک ڈھنگ سے چیک کرنا چاہئیے تاکہ روزانہ جو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے وہ دور ہو۔

ہمارے جموں کشمیر میں یہ پرابلم روزانہ دیکھنے میں آتی ہے کیونکہ ہمارے وہاں گرمیوں میں تو کافی جینریشن ہوتا ہے لیکن جاڑے میں پانی کم ہونے کی وجہ سے جینریشن کم ہو جاتا ہے اور نادرن گرڈ سے تسلی بخش بجلی نہیں ملتی ہے۔ اور لوگ بھی جاڑے میں ہیٹر وغیرہ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اس لئے بجلی کی چوری کرتے ہیں اور اس طرح لیکیجز ہونے کی وجہ سے لوڈ کافی بڑھ جاتا ہے اور شیڈنگ ہو جاتا ہے۔ اس پر آپ کو توجہ دینی چاہئیے۔

سینٹرل گورنمنٹ کے دو پروجیکٹس جموں کشمیر میں چل رہے ہیں، سلال پروجیکٹ اور دل ہستی پروجیکٹس۔ سلال پروجیکٹس کے مینیجمنٹ کو کام ٹھیک ڈھنگ سے کرنے نہیں دیا جاتا ہے۔ اسٹیٹ کی رولنگ پارٹی کی طرف سے پالیٹکل انٹرفیرنس کافی ہوتا ہے جس کی وجہ سے مینیجمنٹ ٹھیک سے کام نہیں کر پا رہا ہے۔ وہاں کے لیبر کو انسٹی گیٹ کر کے کام میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے۔ اگر سلال پروجیکٹ کا کام ٹھیک سے چلے اور سمے پر پورا ہو تو ملک کے آرتھک بھاگ کو کافی لابھ ہو سکتا ہے۔ آپ کو اس کے متعلق ہمارے راجیہ کے مکھیہ منتری اور بجلی منتری سے بات کرنی چاہئیے

کہ اس طرح کی روزانہ پرابلمس وہاں پیدا نہ ہوں تاکہ وہ پروجیکٹ جلدی سے جلدی تیار ہو جائے ۔ اسی طرح میری اسٹیٹ میں جوائنٹ سیکٹر کے چھوٹے پروجیکٹ ہیں ۔ خاص کر میری کانسٹی چوینسی میں پچھلے ۲۰ سال سے کوئی دو میگا وہاٹ کیپیسٹی کا ایک پروجیکٹ اسنکنا ہائڈل پروجیکٹ کے نام سے چل رہا ہے ۔ یہ تین ساڑھے تین کروڑ کا پروجیکٹ پہلے تھا اب وہ سترہ اٹھارہ کروڑ تک پہنچ گیا ہے اور اس سے صرف دو میگا واٹ بجلی آنے والی ہے وہ بھی ابھی تک کمپلیٹ نہیں کر سکے ۔

اس طرح کارگل میں مائیکرو ہائڈل ایک میگا وہاٹ کا پروجیکٹ پچھلے کئی سالوں سے چل رہا ہے ۔ ہمارے لداخ سیکٹر میں بجلی کے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں ان کی ورکنگ بالکل تسلی بخش نہیں ہے ۔ کرپشن حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے ۔ پرائسس ہر سال بڑھتے جا رہے ہیں ۔ آپ پیسے کا الاٹمنٹ کم دیتے ہیں ۔ اس لئے ۲۰ سال سے بھی ادھک میں دو میگا وہاٹ کا پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا ہے ۔ کیندریہ سرکار کو اسے دیکھنے کی ضرورت ہے ۔ اس کو زیادہ ڈھیلے نہیں کرنا چاہئے ۔ میری یہ گذارش ہے کہ آپ کوئی ایسی رقم ایک یا دو سال کے لئے ریلیز کر دیجئے جس بن جائے ۔ یہ نہیں کہ تھوڑی تھوڑی رقم آپ دیتے رہیں اس طرح نیکسٹ ایئر پھر پرائسز بڑھ جاتے ہیں ۔ اس لئے یہ کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا ہے ۔

بجلی سپلائی کے مسئلے میں دو ایک سجھاؤ میں دینا چاہتا ہوں ۔ جتنے بھی ہمارے سپر تھرمل پاور اسٹیشن ہیں یا سپر ہائڈل یا اٹومک انرجی کے جتنے بڑے بڑے پاور اسٹیشن ہیں ان کے جینریشن اور ورکنگ کو کیندریہ سرکار کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہئے اور جتنے بھی اسٹیٹ الیکٹریسٹی بورڈ ہیں ان کو آپ کو پاور سیل کرنا چاہئے ۔ یہ نہیں کہ ہر اسٹیٹ اپنے پاور پروجیکٹ کو پکڑ کر بیٹھے رہیں ۔ ان کی ورکنگ بھی ٹھیک نہیں ہے ۔ کوئی سسٹم کام کرنے کا نہیں ہے ۔ اس کی وجہ سے سارے ملک میں مشکلات آ رہی ہیں ۔ کیوں کہ نادرن گرڈ الگ ہے ویسٹرن گریڈ الگ ہے اور ساؤتھرن گریڈ الگ ہے ۔ اس میں آپ اچھی طرح سے یونیفارملی بجلی سپل کو پائیں گے ۔ جو ڈیفیشینٹ اسٹیٹ ہیں جہاں جینیریشن کی کیپیسٹی نہیں ہے چاہے ہائڈل ہو تھرمل ہو یا دوسرے ہوں جو اس طرح سے ہر ایک کو یونیفارملی پاور مل جائے گی ۔

لیکیج (Leakages) اور ٹرانسمشن لاس ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے اس کو بند کرنے کے لئے بھی سوچنا چاہئے کہ کس طرح سے کم ہو سکتا ہے ۔ ٹرانسمشن لاس کے بارے

میں ریسرچ کر کے دیکھنا چاہیئے کہ اس میں کم سے کم لاس ہو۔ ہمارا ملک بہت بڑا ہے ٹرانسمشن لائن کو ملک کے کونے کونے میں لے جانا پڑتا ہے جس میں کئی جگہ زیادہ لاس ہو سکتا ہے۔ لیکیج کے مسئلے میں بھی دیکھنا چاہیئے۔ . . .

بجلی کے بہت ساری جگہ میٹر ہیں میٹر میں بھی آپ نے منی مم چارجز رکھے ہوئے ہیں اور کئی جگہ فلیٹ ریٹ بھی ہیں۔ آپ فلیٹ ریٹ سے پیسہ لے لیتے ہیں لیکن بجلی وہ یوز کرنے جا رہے ہیں اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ لیکن میٹر میں بھی سسٹم کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ منی مم ریٹ آپ چارج کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارا فلیٹ دو تین مہینے انٹرسیشن میں بند کر کے ہم چلے جاتے ہیں لیکن منی مم چارجز تو دینا ہی ہے اس لئے ہم سوچتے ہیں کہ چلو ایک بتی جلا کر چلے جاؤ اس سے فرق کیا پڑتا ہے منی مم تو دینا ہی ہے۔

اگر کنزیومرز سے منی مم چارجز کی بجائے ایکچول ریڈنگ کے حساب سے چارج کیا جائے تو لوگ کوشش کریں گے کہ بجلی کنزمپشن کم سے کم رکھی جائے۔ آج حالت یہ ہے کہ لوگ ایک بتی کو چوبیس گھنٹے جلا کر رکھتے ہیں کیوں کہ انہیں معلوم ہے کہ اس کی لاگت منی مم چارجز سے زیادہ نہیں ہوگی مجھے آشا ہے کہ منتری مہودے میرے سجھاؤ پر وچار کریں گے۔ اس سے پاور میں بچت ہوگی۔

منتری مہودے جو ایمنڈمینٹ لائے ہیں میں ان کی تائید کرتا ہوں۔

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU (Chittoor) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I welcome the Bill brought forward by the hon. Minister of Energy. He has tried to have uniformity throughout the country. But I am afraid the three per cent surplus will give rise to increase in tariff. I request the hon. Minister to see that the tariff is not raised. When we see the situation in the country, we find that the power distribution is most appalling. When we look to the Press reports, we find : December 31-45 per cent power cut for all low-tension industries in Tamil Nadu ; December 31-Big power cut in Punjab ; January 4-Power crisis in West Bengal ; January 6-Power situation worsens in Haryana, January 8-Power famine haunts Goa ; January 7-Power shortage affecting cement production in Bombay, January 11—54 per cent power cut in Orissa : January 12—Power crisis again in Rajasthan; January 30—Sonepat power cut hits industrial production. It is just like that throughout the country in January itself, in the beginning of the year itself. Therefore, the Minister should see the something is done to maintain the power distribution without any cut.

When we see the capacity and the utilisation of power projects, it is like this :

	Plant Availability	Capacity Utilisation
1973-74	71.3 per cent	50.5 per cent
1974-75	76.3 per cent	52.7 per cent
1975-76	75.9 per cent	51.9 per cent
1976-77	77 per cent	55.3 per cent
1977-78	72.4 per cent	52.7 per cent
1981-82	68.5 per cent	46.5 per cent
1982-83	68.5 per cent	48 per cent
	(from April to November)	

Therefore, the utilisation is very low. The Minister should find out the reasons why the utilisation is so low and he should see that it is rectified because is the generation is not utilised, then the cover-heads will become more and losses will be there.

With regard to live losses, the figures are as follows, for the year 1980-81 : Andhra Pradesh—22.69 per cent, Assam—20.28 per cent, Bihar 21.38 per cent, Haryana-23.6 per cent, Karnataka—22.33 per cent, Madhya Pradesh-22.40 per cent, Nagaland—26.59 per cent, Rajasthan 25.97 per cent, Tripura—33.97%, Manipur—45.76%. Therefore, the line losses are very high and unless the line losses are brought down to at least 10%, I think there will be losses and these losses have to be borne by the consumer. Why ? Therefore, these line losses must be reduced. But the remedy suggested by the Government is that the system improvement must be there. They are not doing system improvement in all the States. Therefore, they have to take it up. But I regret to say that the Government has suggested that capacitors must be installed by the consumers, especially the agriculturists. I am against this because the line losses are there. If there are line losses, capacitors must be based in the transformers and not that the agriculturists should be pressed to have them by the side of the motors. The standard of the motors is not good and the Government should bring a law so that the standard of motors is maintained.

Now we are short of plants and also cables, conductors, transformers and other materials and the Government should start factories to manufacture these things or encourage the private factories or joint venture factories to manufacture these things. Unless we have these things, it is not possible for us to maintain or to go ahead with the projects. There is delay in constructing the projects. For example, in West Bengal, it is said, that a unit which was to be commissioned in 1980 will not come up even by 1985. This is the position. I can tell the Minister that in the Shri Sailam project which is in Andhra Pradesh, I know that for 2 years the money given is not at all sufficient even to pay the salaries of the officials. Therefore, if we see that there are losses in the Electricity Board, the cause is that.

Now, the Government says that 3.1 lakh villages have been electrified—that is 53% of the villages. I say that is not so, for the government definition of electrifying a village is that if any portion of a village is electrified, they say the village has been electrified. If we take that definition, now you know in Tamil Nadu, Andhra and in any other State in our country, there are hamlets also to the villages. There are 15 to 30 villages. Suppose they electrify the centre of the revenue village. Then they say that it is completed. Now, if we take Andhra Pradesh, there are 30,000 hamlets left out ..

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH) : We have recently allowed them to cover the hamlets also.

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU : Thank you, Sir. Then, the Electricity Board takes agreements from the agriculturists and others. I want to say with regard to the agriculturists. The agreement is unilateral. Nearly 30 to 40 signatures are obtained and they do not know what is there. Then it is in English and it is not printed in Telugu or Tamil or any other regional language.

MR. DEPUTY-SPEAKER : If you make this demand, the Telugu Desam Government will immediately do it.

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU : Unilaterally they say that under any circumstances, we have to pay the minimum charges. Suppose there is breakdown of the project we are not going to get electricity. The crops will wither away. The Electricity Board is not having any responsibility or obligation to give them the compensation. Therefore, what I say is that it must be bilateral and not a unilateral agreement. This unilateral agreement must be changed so that the agriculturists may not be put to any loss. (*Interruptions*) Suppose there is a breakdown in the system. For 10 or 15 days there is no electricity ; the crops will wither away. Then who is responsible for it—not the peasant but it is the Administration which is responsible. It is the Electricity Board which must take the responsibility and it must be under obligation to pay compensation to the peasants. That is my demand.

In many States, we are told that we pay the minimum charges. Suppose there is famine ; there is no water in the well. Even then they say these minimum charges have

to be paid. There is no provision for it in many States. Therefore, I request the Government to see that when there is famine and when it is declared by the Revenue Department, then, in that area, the minimum charges have to be waived. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. A.K. Roy. You can start. We shall adjourn at 1 O'Clock.

SHRI A.K. ROY (Dhanbad) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, the Minister of Energy hds the reputation of being an energetic minister. Through this Bill, he has practically attempted some magic. Sir, we and you might have read the famous Book of Genjsis which contains the following questions.

"Let there be light ;
And behold there is light".

Here it is like these.

"Let there be surplus ;
And behold that surplus".

We are all expecting some electricity from the Electricity Board. In Bihar, it is all darkness. It is reported that you won't get electricity supply to agriculture or to small scale industries or even to your house. What is more is this. Before I come here, it was reported that the colliery-mines are getting drowned because of the rise in the water levels. They are not getting electricity continuously for six or even hours. The levels of Sudamdih mine are under water. All the small scale industries are facing difficulties and they are getting closed down. Due to the recent rise in tariff rate the entire wheat grinding machinery is put to great difficulty. You will be surprised to know that grinding one kilo of wheat costs one rupee. That is the situation that has been created.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Roy, you may continue after lunch.

13.00 Hrs.

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Seven minutes past Fourteen of the Clock.

[SHRI R.S. SPARROW -- in the *Chair*]

ELECTRICITY (SUPPLY) AMENDMENT BILL—*Contd.*

MR. CHAIRMAN : Now, Shri A.K. Roy to continue his speech.

SHRI A.K. ROY (Dhanbad) : Mr. Chairman, I was submitting to the House how the days of darkness had come to Bihar and how the hon. Minister, through this legislation, wanted to create surplus out of the State Electricity Board without getting electricity. Sir, in our area, specially in the Dhanbad industrial belt, both the State Electricity Board and the D.V.C. have failed resulting in the closure of the smallscale indutrises and drowing all the mines. Now, added to the trouble, the Bihar State Electricity Board has increased the tariff. That has created some more problems and complicatious. I would like to refer to this matter because this Bill hints at increasing the tariff. Otherwise, how surplus could be created ? The surplus can be created by increasing the efficiency or by increasing the tariff. Here, there is no direction, no hint and no transmission line. Now, how will you increase the efficiency ? So, naturally, we are to presume that the whole stress is to create surplus by increasing tariff and already a situation has been created. I would like to quote here the editorial of the 'Indian Nation' dated 24th July, 1983. According to a report published in the local dailies, the charges for 527 units of electricity consumed by an industry come to Rs. 402.63 in May ; but after the enhancement of the tariff, the same consumer had to pay Rs. 1087.78 for the 502 units of electricity consumed in the month of June. In the case of wheat grinding, the rate is likely to go up to 50 paise per kg. from 20 paise per Kg.

This is the position in Bihar. One unique feature of the debate is that Members from all parties and from all the States uniformly expressed their concern at the state of affairs in the Power sector. And there are reasons for that. If you read the neswspapers, you will find that due to non-availability of power, the fertilizer plant in

Talcher and Ramagundam are not operating. For want of power, the steel plants at Rourkela and Bokaro are not working. BCCL's collieries are also not working in other places. Agriculturists are complaining, industrialists are complaining, and we do not know how to calculate the loss of industrial production because of non-availability of electricity. You know that by generating Rs.1/- worth of electricity, you can produce Rs. 15/- worth of industrial goods. In this way, the country is losing heavily.

This situation has not come about suddenly. We wanted some legislation, and some direction so that we can correct this sad position. That is why we have observed that though the scope of the Bill is very limited, it desires the legitimization of the Venkataraman Report of 1964 regarding the financial position of State Electricity Boards. But Members themselves enlarged the scope. Ultimately, the discussion has become a general discussion on power. This is because of the serious concern felt by all the Members.

It is not as if we have reached these days of darkness suddenly. It is the cumulative effect of neglect of the power sector. To some extent, we are deceiving ourselves in the matter of power sector. In the 2nd Plan, we were 35% behind our target, i.e. in the matter of capacity addition. In the 3rd Plan also, we were 35% behind the target. In the 4th Plan, we were behind by 51% in creating capacity. In the 5th Plan, our performance has been dismal. I feel that in the 6th Plan, we will not be able to attain even 60% of what we had planned at the beginning. It means that we had planned for some 20000 MW. of electrieity ; but we are unlikely to go beyond 12000 MW. That is the position.

There is another development due to which this Bill has come. The State Electricity Boards have to invest about Rs. 1400 crores in eleetricity. Up till now, only Rs. 7000 crores could be invested. The question is whether we can get more funds. Funds cannot be obtained simply by coming out with the Bill. We have to go deep into the tarlff. The TRD loss which was 15%, had grow to 20%, then to 22% and now it is 25%.

In this way, capacity utilization in 1976-77 was 56 per cent. After that it came down. Lat year, it was 49 per cent. This year, it is only 42 per cent, which means if you plan for 100 MW generation capacity, actually you are creating 60 MW because your performance is 60 per cent and your capacity utilization is 42 per cent. Out of 60 MW, you are getting electricity of 40 MW. The loss of TRD has increased from 15 per cent to 25 per cent. So, ultimately, from our expectation you are ending up with 25 per cent MW electricity, so far as the consumer is concerned ; that means a plan of 100 MW is ending upwith 25 MW, so far as the consumer is concerned. That is why the figure of the Ministry of Energy is not being believed ; even the other Ministries are not believing this Ministry. That is why they are making captive power plant. Why if their figures are correct ? The overall shortage of electricity in the country is decreasing from 16 per cent to 12 per cent, 12 per cent, 9.2 per cent and then they are claiming that it is 4.2 per cent. If it is decreasing each year, then why there is a rush for all the public sector units to have a captive power plant. They could have depended on them. Today, the steel industry is making their captive power plant. The fertiliser industry is making their captive power plant. There is a talk that the coal industry should also have a captive power plant ; and there will be time when the Minister of Energy will also plan for a captive power plant within the power industry.

I want some direction should be there, as hon. members expect, either through the Bill or through some statement so that we can get some idea how the government is going to tackle this power crisis in the country, which is increasing.

This Bill intends to create a surplus. But what is the position of the State Electricity Boards now. I am taking up the capital structure of the State Electricity Boards. It depends on three things : (1) Loan taken from the State government ; (2) Loan taken from the markets ; and (3) internal resources. This Bills wants that the internal resources should be enlarged so that it becomes less and less dependent on others. Now the U.P. State Electricity Board has taken loan of Rs.

1759.24 crores from the Government and the total loan is Rs. 2138.51 crores. This is the position on 31.3.80. The Bihar SEB has taken Rs. 403.5 crores and the total is Rs. 643.71 crores. The West Bengal SEB has taken Rs. 277.73 crores. Then what are the dues of the State Electricity Boards ? In September 1980, as far as the U.P. SEB is concerned, it is Rs. 83.67 crores; Bihar—Rs. 71.32 crores and West Bengal—the figure is not available. (*Interruptions*) That is the answer that you have given in your Unstarred Question.

The figure for West Bengal is not available.

That is the answer you have given to this Unstarred Question.

SHRI CHITTA BASU (Barasat) : West Bengal has gone out of the bag.

SHRI A.K. ROY : The figures are not available in the reply.

SHRI GIRDHARI LAL VYAS (Bhuilwara) : Figures are not available.

SHRI A.K. ROY : The figures are not available in the answer given.

SHRI CHITTA BASU : West Bengal figures are not available.

SHRI A.K. ROY : For Bihar and Uttar Pradesh the figures of losses I have already given. What is the loss suffered by the State Electricity Boards ? That is the financial position of the Boards. This deals with their financial position. The losses of the State Electricity Boards till the 31st March, 1979, are as follows :

U.P. State Electricity Board, the cumulative loss was Rs. 422 crores and 71 lakhs.

Bihar State Electricity Board : Rs. 52 crores and 94 lakhs West Bengal : Rs. 5 crores and 91 lakhs.

Only State Electricity Boards of Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka, Rajasthan and Madhya Pradesh, were earning profit. Now, this position has also gone down. What is the latest position ? The latest position is, the picture has become worse since then. The cumulative losses of the Boards have gone up, to the tune of Rs. 3,600 crores in the first three years of the Plan. In the first three years of the Plan. And, in 1982-83 alone the cumulative losses of the Boards would be about Rs. 1,500 crores. Rupees one thousand five hundred crores. Let us see how through legislation, through this Bill the whole thing can be cured.

I would like to say that the State Electricity Supply Act, 1948, also in Section 59 stipulated, and directed, that the Boards should be autonomous and they should regulate their functions. Autonomous and they should regulate their functions in such a way that they should earn profits and should not run into losses. This was thus provided in the basic law, the legislation which brought all these State Electricity Boards into existence. After that amendment of 1978, a direction was given to them that a surplus should be created. That surplus should be created as specified by the State Governments, but since 1978, when the Janata Government was there—no State Government specified any surplus and no surplus was ever created. That was the fate of that legislation. Now the present amendment of 1983 has practically concretised that term surplus, 'suitable surplus' by 3 per cent should be created, according to the Venkataraman Report. But I would like to put one question to the Minister. What would happen if a State Electricity Board does not create the surplus, or does not make profits ? Is there any provision in your laws or will it remain like your 1978 legislation ? In that legislation also this provision was there about suitable surplus to be created, that profits should be earned, as specified by the State Governments. Now, no State Government has so far specified even now. No State Electricity Board has created surplus. What action could you take against them ? Similarly, you are making a legislation that 3 per cent profits must be made by them. If they do not make, what action are you taking ? What is the use of passing a legislation which can never be enforced ? That is the first thing. And, there is no provision here to say that they should create a surplus. And, what is the priority for the distribution of the surplus power ? What is the method by which the surplus could be created making use of the internal resources. But, I would like to know what action you take, if that does not happen ? The State

Electricity Boards lack everything. Now everything has become a part of the Centre State relations. The Rajadhyaksha Committee says that the power crises has already started. We are already fed up with so many crises. Now this power crises has also become a part of the Centre-State relations. The boundary dispute is already a part of the Centre-State relatsons. Now, the division of river waters has become Centre-States relations. Tomorrow, the debate will also become the Centre-States relations. That is how you are keeping the Centre-States relations. How would you expect that such things could be curbed? What is the way out so that the hon. Minister can gain the confidence of the States ? If there remains a constant air of suspicion between the Centre and the States, I think, no work can proceed. I would like to know from the hon. Minister as to what concrete steps he is going to take so that the air of suspicion between the relations of the States and the Centre could go. This is a serious thing. The Rajdhyakaha Committee was formed in Janata Party time and the report was given in Congress time. The report says that any step taken in solving the problem of power is considered as infringement on the rights of the States. The accusation against the Centre is that it is curtailing the autonomy of the States. And against the States, the accusation of the State Electricity Borads is that the States are curtailing the autonomy of the State Electricity Boards. As per the Constitution only the Chairman and the Members could be appointed by the Government and the rest of the things are the right of the State Electricity Boards. But here even a small Class IV employee could not be recruited ; even a engineer could not be transferred without the Government's approval. So, this is the position.

SHRI XAVIER ARAKAL (Ernalculam): What is your suggestion ?

SHRI A.K. ROY : My suggestion is that the Central Government should strengthen the Central Electricity Authority properly. If it acts in a proper way and helps in removing the Bills of the State Electricity Boards, then the atmosphere of suspicion between the Centre and the States that the Centre is interfering, would be removed.

SHRI BIKHU RAM JAIN (Chandni Chowk) : What is the difference between helping and interference ? (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : You were to take 9 minutes. You have taken 22 minutes. Very kindly be a little considerate because others have to speak. You have given a good talk. (*Interruptions*)

SHRI A.K. ROY : You know that the power plant is a capital based industry. It does not need many people to run a plant. For example, in Bihar the total installed capacity is 940 MW but it is producing 250 MW. The Central Electricity Authority can have a composite team of instrumentation. The BHEL will look after the machines : the power engineers will operate them and the coal specialists will see the quality of the coal. That may constitute a Task Force. They may go, they may take one or two units and they could show how it should operate. Why don't you do it ? Secondly, can you come forward with a Bill which will say that if the capacity utilisation of a particular State Electricity Board goes down a particular level, then the Central Government, the Central Electricity Authority will be obliged to interfere in that way.

My next point is that in England the transmission and generation are separate. Since the entire Electricity Supply Act has been enacted imitating what was in England, so, I would like to know whether the Government will come out with a Bill which will separate the two ?

MR. CHAIRMAN : Thts is a vast subject, Mr. Roy. It will not finish like this and you seem to be speaking very well.

SHRI A.K. ROY : I come from an area where the State Electricity Boards are there, the D.V.C. is there, everything is there. So I could see and tell.

Another point I will like to say is that political appointments must be stopped. That is the root of all corruption and all inefficiency there.

Lastly, you have to restore the true autonony of the State Electricity Boards.

MR. CHAIRMAN : All right, that is enough. We have got a very fine share of your views and I think it is enough for the

Minister of digest.....

(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Don't spoil your speech now. Don't let me come to the Bell.

SHRI A.K. ROY : Last point, Sir. We cannot come out of this darkness by increasing the tariff and by emphasising the importance of financial portion of State Electriciry Boards but the increasing the efficiency and emphasising the productivity portion of the State Electricity Boards.

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : सभापति महोदय, यह जो विधेयक पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। बिजली की समस्या काफी विकट होती जा रही है। बिजली के बिना कोई भी क्रिया-कलाप नहीं चल सकता, चाहे वह औद्योगिक हो, कृषि से सम्बन्धित हो या ट्रांसपोर्ट से सम्बन्धित हो। बिजली के लिए जितनी कठिनाई देश में आज पैदा होती जा रही है, उतनी इससे पहले कभी नहीं थी, क्योंकि जैसे-जैसे हम प्रगति की तरफ बढ़ते जा रहे हैं—ज्यादा उद्योग लग रहे हैं, खेती में भी बिजली की आवश्यकता लगातार बढ़ती जा रही है—उसके हिसाब से बिजली की पैदावार नहीं बढ़ रही है। एन०टी०पी०सी० और स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड्ज द्वारा पिछले तीन चार वर्षों में जो कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं, वे आठ दस वर्षों से पहले तैयार नहीं होंगे और उससे पहले वहां से बिजली सप्लाई नहीं की जा सकेगी, लेकिन तब तक बिजली की मांग इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि फिर जिस स्थिति में आज हम हैं, उसी स्थिति में फिर 8-10 साल बाद हम अपने को पाएंगे।

सभापति जी, हम बिजली के जिस बिल पर बहस कर रहे हैं, उसका मकसद तो बहुत ही सीमित है, जिसके बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपनी राय जाहिर की है। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और केन्द्रीय सरकार का कन्ट्रोल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर नाम-मात्र का होता होता है। अभी मैं अपने साथी श्री ए०के० राय का भाषण सुन रहा था। उन्होंने इसमें स्टेट और सेन्टर के रिलेशन्स की बात कह दी। इस समय हमारे देश में सेन्टर स्टेट रिलेशन्स की चर्चा इतनी संवेदनशील हो गई है कि अगर कोई छोटी सी बात भी कहनी है और कोई ठीक बात भी कहनी है, तो डर लगता है कि पता नहीं उसकी क्या प्रतिक्रिया लोगों में हो जाएगी लेकिन वास्तविकता यह है कि आज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भ्रष्टाचार के अड्डे बन गये है और अनुशासनहीनता उनमें चरम सीमा पर पहुंच चुकी है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : बिहार में वह बहुत ज्यादा है।

श्री जैनुल बशर : बिहार में है और उत्तर प्रदेश में भी है और दूसरे प्रदेशों में भी है और किसी के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : बिहार लाइलाज है।

श्री जैनुल बशर : बिहार जहां लाइलाज हो रहा है, वहां उत्तर प्रदेश में भी यही हालत है। अभी पिछली कन्सलटेटिव कमेटी, एनर्जी मिनिस्ट्री में एक सवाल उठाया गया था कि उत्तर प्रदेश में जो बिरला का कैप्टिव पावर प्लान्ट है हिन्डालको, वह अपनी इन्स्टाल्ड कैपेसिटी का 85 प्रतिशत पैदा करता है। जब कि उत्तर प्रदेश का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड केवल 40 प्रतिशत ही बिजली पैदा करता है। इस तरह से आप यह देखें कि जो प्राइवेट सेक्टर है, वह अपनी इंस्टाइल्ड कैपेसिटी का सरकारी क्षेत्र के बिजली बोर्ड के मुकाबले में दुगने से अधिक बिजली पैदा करता है। आज आप किसी भी जिले में चले जाइए, उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में चलें जाइए, वहां आप यह पाएंगे कि इंजीनियर का जो दफ्तर है, उसका घेराव हो रहा होगा और भूख हड़ताल हो रही होगी एक ट्रांसफर पर, एक पोस्टिंग पर हड़तालें हो जाती हैं। इतनी अनुशासनहीनता आज पूरे इलेक्ट्रिसिटी बोर्डों में है। चाहे इन्जीनियर हो

चाहे लाइनमैन हों, चाहे श्रमिक हों और चाहे किसी भी केटेगिरी के हों, यहां तक कि चीफ इन्जीनियर के लेविल के अधिकारियों में भी बड़ी अनुशासनहीनता हो गई है और मैं ऐसा समझता हूं कि जो स्थिति आज उत्तर प्रदेश और बिहार में है, वही स्थिति कमोवेश और भी स्टेटों के इलेक्ट्रिसिटी बोर्डों की है और एक भ्रष्टाचार का माहौल इतना अधिक हो गया है कि उसके रहते हम बिजली में सुधार की आशा कैसे कर सकते हैं और जब इस सदन में बिजली बोर्डों के खिलाफ कुछ कहते हैं या उनकी निन्दा करते हैं, तो हमारी केन्द्रीय सरकार उसमें अपना अहित फील करती है। अभी मंत्री जी उठेंगे और अपने जवाब में कह देंगे कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्डों की राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है और हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। हम तो वहां पर अपने एक्सपर्ट्स भेज कर उनको सलाह दे सकते हैं कि वे कैसे बिजली पैदा करें और उनमें जो खामियां हैं, उनको ही हम बता सकते हैं। उनको कुछ वित्तीय सहायता दे सकते हैं और इसके अलावा उनके इन्तजाम में हम कुछ दखल नहीं दे सकते। तो इसका इलाज क्या है ? आखिर बिलजी एक अहम मामला है, जिसके बिना देश तरक्की नहीं कर सकता, देश प्रगति नहीं कर सकता, खेतों में गल्ला पैदा नहीं हो सकता और कारखानों में काम नहीं हो सकता। इसलिए इस महत्वपूर्ण मामले में हम क्या करें। सेन्टर-स्टेट रिलेशन्स की बात करें या हम अपने को बिल्कुल खत्म करके इस प्रगति के पहिये को रोक दें। राज्याध्यक्ष कमेटी की रिपोर्ट की बात कही गयी। उसने सही रिपोर्ट दी है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जैसे ट्रांसपोर्ट के मामले में, रेलवे के मामले में, देश में एकात्मकता बढ़ती गई है, देश को एक जोन माना गया है। उसी तरह से आज पावर के मामले में, बिजली के मामले में देश को एक जोन मानना पड़ेगा।

बिजली दो चीजों से बनती है : थरमल पावर स्टेशंस में कोयले से बिजली बनती है और हाइडल पावर प्लांट्स में बिजली पानी से बनती है। अब हम एटोमिक पावर प्लांट्स भी लगा रहे हैं। लेकिन अधिकतर बिजली पानी से बनाई जाती है क्योंकि कोयला सारे देश में हर जगह पर नहीं मिलता है। कोयला देश में कुछ सीमित जगहों पर मिलता है। उसकी खानें कुछ स्थानों पर ही हैं जहां से कि कोयला निकलता है। हमारे देश में जो कोयला निकलता है वह उतना अच्छे किस्म का नहीं है जिससे कि बिजली बनाई जा सके। हमारे यहां निकलने वाले कोयले में ऐश कन्टेंट ज्यादा होता है। जिस कोयले से बिजली बनती है वह कोयला हमारे देश में कम है। फिर कोयले की ढुलाई का भी सवाल है। कोयला रेलवे वेगनों द्वारा ढोया जाता है। इस तरह जो कोयले की ढुलाई होती है उसमें ऐश भी ढोया जाता है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि हम थरमल पावर प्लांट्स कोल हेड्स पर बनाएं। कोयले की ढुलाई में, उसके ट्रांस्पोर्टेशन में खर्चा ज्यादा बैठता है, बिजली के लाइनों द्वारा ट्रांसमीशन में कम खर्चा बैठता है और बिजली लाइनों द्वारा आसानी से ट्रांसपोर्ट की जा सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम कोल हेड्स पर अपने थरमल पावर स्टेशन बनायें और देश भर में चारों तरफ बिजली को पहुंचाएं। इस तरह से बिजली की पूर्ति अच्छी तरह से हो सकती है।

दूसरी ओर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स द्वारा हाइड्रो ईलेक्ट्रिक बनाई जा रही है। उसमें स्टेट और स्टेट के बीच नदियों के पानी के बटवारे के बारे में झगड़े हैं। जहां पर हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्लांट् हाइड्रो बिजली बनाने के कारखाने लगाये जाते हैं उनके बारे में स्टेट स्टेट के बीच विवाद वर्षों से चले आ रहे हैं। ये विवाद न सुलझ सकते हैं न सुलझ रहे हैं। अगर ये सारी चीजें केन्द्रीय सरकार के हाथों में आ जाएं तो इस मामले में देश बहुत आगे बढ़ सकता है। कोल हेड्स पर थरमल पावर प्लांटस लगा कर, बिजली के कारखाने लगा कर बिजली को सारे देश में भेजा जा सकता है।

हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी काफी सस्ती पड़ती है। यदि उसके पावर प्लांट्स भी केन्द्रीय सरकार के हाथ में आ जाएं तो वहां भी अधिक बिजली पैदा कर के देश में पहुंचाई जा सकती है। जहां केन्द्रीय सरकार बिजली की पैदावार करे वहां वितरण का काम राज्य सरकारों को दिया जा सकता है कि वे बिजली की सप्लाई कंज्युमर्स को करें। लेकिन जब तक बिजली की जेनरेशन का काम केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में नहीं लेती है तब तक बिजली की पैदावार की स्थिति हमारे देश में अच्छी नहीं हो सकती है। बिजली की पैदावार का काम केन्द्रीय सरकार के हाथ में आने से सभी को फायदा पहुंच सकता है। अगर हम इसी तरह से राज्य सरकारों पर बिजली की बात को छोड़ते रहेंगे तो इस सदन में हम ऐसे ही भर्त्सना करते रहेंगे, केन्द्रीय सरकार और मन्त्री जी को भला बुरा कहते रहेंगे जिनके कि पास इसका कोई जवाब नहीं है। इससे बिजली का कोई मसला हल होने वाला नहीं है।

मैं इन सुझावों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : सभापति महोदय, हमारे सामने जो बिल है, इसका मकसद बहुत साफ है। इसके बारे में कोई लम्बी चौड़ी बात मुझे नहीं कहनी है। 1948 के बाद इस एक्ट में कुछ परिवर्तन आया। 1978 के परिवर्तन के बाद ऐसा अनुभव किया गया कि इसमें कुछ लैप्सेस रह गए हैं। इनको ठीक किया जाना चाहिए। मेरे खयाल से लैप्सेस को ठीक करने के लिए जो बात इस बिल में कही गई है उससे सारा सदन एक मत है। मैं कुछ सुझाव इस बिल के संबंध में देना चाहता हूं।

केवल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्डों की कमियों को हाई लाइट करें और सरकार द्वारा बिजली की 40 संस्थाओं के बारे में चुप रहें तो यह उचित नहीं होगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। बिहार राज्य पोटेंशियल राज्य है इसमें दो राय नहीं है। वहां पर कोयला सबसे अधिक है और पानी भी सबसे अधिक है। इंटरनल रेसोर्सेस अधिक हैं और किसी न किसी कारण से गरीबी भी यहां पर सबसे अधिक है। मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि इस गरीबी को मिटाने के लिए जो कंसल्टेड एफर्ट्स होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया, चाहे सरकार किसी भी दल की रही हो। एक उदाहरण सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहलगांव का देना चाहता हूं। सबसे ज्यादा वैज्ञानिक तरीके से आफिशियल लेवल पर बिहार के इस पोटेंशियल एरिया को इग्नोर किया गया। किसने इग्नोर किया यह मंत्री जी बताएं। मेरे पास जो कागजात हैं उनसे मैं साबित कर दूंगा कि सरकारी नौकर इसी तरह की योजनाएं बनाते हैं। राजमहल में कोल एक्सप्लोरेशन के लिए विचार किया गया। उस वक्त बताया गया कि 3000 मिलियन टन कोयला राजमहल में छलपटिया इत्यादि में एवलेबल है। गंगा और कोसी का पानी भी वहां पर मौजूद है। वहां पर लीन पीरियड सरकुलेटरी सिस्टम वाटर कूलिंग प्रासेस के लिए ले सकते हैं। मैं एक एक्सपर्ट से बात कर रहा था। उसने कहा कि कहलगांव इज सब्जेक्ट टू इरोजन। मैंने पूछा कि क्या आपने कहलगांव देखा है। उसने कहा कि हां मैंने देखा है। मैंने जियालाजिकल मैप लाकर दिया। भागलपुर से लेकर कलकत्ता तक जो सड़क जाती है, कहलगांव उसके दाहिनी ओर पड़ता है। 120 वर्ष से कहलगांव से लेकर कलकत्ता तक जो रेलवे लाइन जाती है वह तो कभी पानी में नहीं डूबी। कहने लगे कि यह प्वाइंट तो हमें याद ही नहीं रहा। यह बात और किसी ने नहीं कही तत्कालीन इलेक्ट्रिसिटी सेक्रेटरी ने कही। सायल टेस्टिंग के बारे में कहा गया कि कहलगांव इज सब्जेक्ट टू इन्डेशन। वहां मिट्टी बहुत ज्यादा लगेगी। जब मैंने रिपोर्ट देखी तब इस बात का पता चला।

I have asked many Questions on this subject. This is the answer to my Unstarred Question No. 1176, dated 24-2-1981 :

"The river Ganga in Murshidabad

district of West Bengal downstream of Farakka barrage has been causing erosion along its right bank."

कहा जा रहा है कि कहलगांव में इरोजन होगा। अर्थ सबस्टांस राकी बेस पर बना हुआ है, इसलिए इनअनडेशन का कोई सवाल नहीं है। जो रिपोर्ट आई है उस में सिविल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट को किस प्रकार से ट्विस्ट किया गया है और कहलगांव को पीछे फेंकने और दूसरों को आगे लाने का कार्य किया गया है इसको आप देखें :

"The minimum formation level in the plant area (that is in Kahalgaon) will be kept at RL + 34 m. whereas the area which is already higher than RL + 34 will be levelled in different terraces such that the filling and cutting work more or less balances out and does not require import of earth for filling or disposing off of the surplus earth."

श्री मोरार जी भाई से प्रश्न भी किया गया था, उनको भी लिखा गया था। उन्होंने तत्कालीन एम. पी. श्री रामजी प्रसाद सिंह को लिखा कि चूँकि फरक्का में अर्थ फिलिंग में बहुत ज्यादा मिट्टी लगेगी तेरह मिलियन क्यूबिक मीटर लगेगी इसलिए कहलगांव ठीक साइट नहीं है। सच्चाई यह है कि कहलगांव में अर्थ फिलिंग के लिए मिट्टी कहीं बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है। यहां इफरात में मिट्टी है। पानी भी इफरात में है। ड्रेसिंग कर देंगे तो ऊंचाई की मिट्टी काटकर नीचे डाली जा सकती है और सारी समस्या का समाधान हो जायेगा।

जो योजना 1973 में कंसीव की गई है जहां कोयला भी उपलब्ध है किन सरकमस्टांसिस के अन्दर सेंट्रल इलैक्ट्रिसिटी आथोरिटी ने कहलगांव को प्रायोरिटी नहीं दी यह भी इनवैस्टीगेशन का विषय है। राज्य सरकार को दोष दे देने से काम चलने वाला नहीं है। कहलगांग को कैसे पीछे धकेला गया इस पर यौब होनी चाहिये। अस्सी किलोमीटर से कोयला पहुंचाना ठीक रहेगा या बारह से तीस किलोमीटर से, इसको भी देखा जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि प्लानिंग में कहीं न कहीं कोई डिफैक्ट है।

प्लेसिंग आफ दी सुपर थर्मल पावर स्टेशन के बारे में मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। लेकिन आप देखें कि सिंगरोली मिर्जापुर विन्ध्याचल कम्प्लेक्स में शायद बीस हजार मेगावाट टोटल कंपेसेटी का आप लगाने जा रहे हैं। पानी कहां से आयेगा ? बिहार का गला काट कर आरा, पटना, बक्सर आदि जगहों जो पानी सिंचाई के काम आता है उस पानी को रोक कर आप थर्मल पावर स्टेशन में ले जाएंगे और एक का जो लाभ है वह दूसरे का घाटा होगा और हिसाब बराबर हो जाएगा। मैंने 4 जून 1982 को एक पत्र लिखा था और उसमें मैंने चौधरी साहब को साफ लिखा था।

"Although this project (Kahalgaon) was cleared by the Central Electricity Authority quite some time ago, still no provision for this project has been made in the Sixth Five Year Plan nor have any serious efforts been so far made for securing necessary financial and technical assistance for the project either from the international agency i.e. World Bank or for entering into a bilateral agreement with some foreign country."

श्री बिक्रम महाजन के जो जवाब हैं 1980, 1981 और 1982 में उनको आप देखें। उन्होंने कहा था कि कहलगांव का सुपर पावर थर्मल स्टेशन तीन महीने में, चार महीने में लगने जा रहा है। तमाम पत्रों को पढ़कर मैं सदन का समय लेना नहीं चाहता हूं। यह पार्लियामेंट का रिकार्ड है। कृपा कर आप इनको देखें कि किस किस डेट को आपके मंत्रालय के भूतपूर्व मंत्रियों ने हमें आश्वासन दिया था कि कहलगांव का थर्मल पावर स्टेशन बनने वाला है।

परसों कालिंग स्टेशन का जवाब हुआ था और उसमें यह आश्वासन दिया गया था कि हम इसको प्रायोरिटी देंगे। शिवशंकर साहब ने इसी सदन में जो बात कही थी मैं उसको आपको याद दिला देना चाहता हूं।

माननीय शिव शंकर ने क्या कहा था डिबेट के रिप्लाई में :

> "Some hon. Members from Bihar raised the question about Pahalgam. They also referred to the statement made by the then Minister of Steel in 1980. I may bring to the notice of the House that Central Electricity Authority had given a final clearance in March, 1981. But the problem was lack of funds. Efforts are being made to explore various avenues to find the funds and this project of Pahalgam has been given the top priority in 1983-84."

मैं साबित कर रहा हूं कि ऐश्योरेंस और टैक्नीकल ऐडवाइस में कितना मतभेद होता है, किस प्रकार से गुमराह किया जा रहा है। ऐश्योरेंस सर्वश्री महाजन, शिव शंकर और चंद्र शेखर बाबू ने दिया, लेकिन आज उन्हें कहना होगा कि कहलगांव के बाद किन योजनाओं को लिया गया चाहे वह रशियन, अमरीकन, या इंगलिश कांलैबोरेशन से हो ? किस कोलेबोरेशन से कहलगांव को किन टर्म्स पर आप लेने जा रहे हैं ? हर सुपर थर्मल पावर स्टेशन में फौरन कोलेबोरेशन है। किस दिन कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन में हाथ लगने जा रहा है ? कौन सा ऐसा सुपर थर्मल स्टेशन है जिसको बिना हाउस में कमिटमेंट के छठी योजना में शामिल किया गया और कहलगांव को पीछे धकेला गया यह मन्त्री जी हमें अपने जवाब में अवश्य बतायें ? अगर आप हमें यह आश्वासन दे सकेंगे कि निकट भविष्य में आप कहलगांव स्टेशन को शुरू करने जा रहे हैं तो इससे उस क्षेत्र के लोगों की आस्था आप पर रहेगी और हम लोग आपको दुआ देंगे कि कम से कम पूर्वांचल को भूटान, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल, मेघालय, असम और उत्तर प्रदेश को कहलगांव स्टेशन से बिजली फीड कर सकेंगे और लोगों को बिजली मिल सकेगी यही मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं और चाहूंगा कि मन्त्री अपने जवाब में इस बारे में अवश्य कहें। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल की ताईद करता हूं।

SHRI CHITTA BASU (Barasat) : Mr. Chairman, Sir, as desired by you I will be very brief.

Most of the points have already been covered. The only point which I want to drive at is that almost all the memders who have taken part in this debate have not approved of the spirit behind the Bill in spite of the fact that they have at the end used the rhetoric that they are supporting the Bill. My request to the hon. Minister would be to kindly go into the spirit in which the members have so far spoken. And the spirit is the disapproval of the spirit underlying the Bill.

My burden has been lessened to a very great extent by many speakers while they have discussed the financial performance of the SEBs. I would only mention an editorial comment made by the *Economic Times* of July 6, 1978. I quote :

> "According to figures available, against the total investment of about Rs. 2000 crores in the SEBs during 1977-78, the losses suffered by them aggregated a little less than half that amount. U.P. suffered the highest loss followed by Bihar and Punjab ; only Maharashtra achieved a surplus."

This shows the tremendous losses the SEBs have suffered.

Secondly, I want to quote from another editorial comment of the *Financial Express* of April 4, 1983.

15.00 hrs.

They say :

> "In other words, not only have they (SEBs) failed to meet their current account expenses but they have eaten into their own capital base."

This, in short, is the economic position of almost all the State Electricity Boards. This Bill comes in this context. The Bill proposes to statutorily fix a three per cent surplus in all the SEBs. I would only implore upon you, Mr. Chairman to advise this House from the Chair whether the House should enact a legislation which cannot be enforced. Having regard to the fact that almost all the SEBs have got such a distressing financial position, how can you expect

that all the SEBs will liquidate or wipe out the losses so far incurred, repay the loans and then generate a three per cent surplus ? This is moonshine. This is an impossibility. Therefore, I would implore upon you, Sir, being the guardian of the House to advise this House not to enact a legislation which cannot be implemented. I would say that the House should come to realise that they are going to approve a measure which cannot be enforced. As for myself, I do not like to involve myself in that kind of, what I would say, parliamentary crime because it will not be possible to enforce this. Nor does the Bill contain any penal measure. You say, statutorily, a three per cent surplus has to be created, but you do not mention anything about any penal measure. The House should know, having regard to the financial performances of the SEBs, that it is impossible to enforce this legislation. Therefore, my first point is this. Do not force on this House, by the use of your majority, by taking advantage of, what I would say, lack of responsibility on the part of the Members adorning those seats—do not take advantage of this weakness because they do not have the voice to speak out though they themselves know that this is a measure which cannot be enforced—do not bulldoze a measure which the Government cannot enforce. That would be rather landing the Parliament in a situation in which no Parliament should agree to land itself (*Interruptions*)

AN HON. MEMBER : How can you say that ?

SHRI CHITTA BASU : Because the Bill is like that. You cannot enforce it. And if you cannot enforce it, why do you agree to legislate this ? I just appeal to your conscience. Are you in a position to assure, apart from political affiliations, that this can be enforced ? From any commercial point of view, can you come to this position and say that the measure which youare going to enact can be enforced ? If you say 'yes', then with pleasure vote for it. But my conscience knows that it is not a thing which can be voted. I appeal that Parliament should not allow itself to land in a position in which its own measures cannot be enforced and with Members voting for it knowingly, with the knowledge, that this thing is being done. I should implore upon the Minister to take note of this.

My second point is very simple. The hon. Minister is on record to say that the Crntral Government is not going to pay anything in order to wipe out any loan. There is no financial assistance from the Centre so far as the statement goes. Now instead of fixing up a statutory surplus in that way in a statute, may I request the hon. Minister as to what is needed to be done. One is the need to strengthen the SEBs organisationally through measures designed to promote professionalism and specialisation. That is to be done. That is not being done. In some cases the Board's functions are being hampered by imposing certain people who do not know anything about them. Other things can be done. Though in a state of statutorily fixing a surplus of this nature, many suggestions have come and I have also got some which I do not want to give for want of time, I want the Government to strengthen the SEBs and help them to the extent possible so that they may stand on their own feet and see that the power position is improved.

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : चैअरमैन साहब, इस ऐवान के सामने आज जो इलेक्ट्रिसिटी एमेंडमेंट बिल पर बहस चल रही है, उसके बारे में पहली बात तो मैं यह बताना चाहता हूं कि सबसे पहला इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 में बना था और उस वक्त के एक्ट में जो आराज व मकासिद थे, उनमें यह था : constitution, financial performance and accounts of State Electricity Boards.

उसमें इस बात पर जोर दिया गया था और यह बात कही गई थी। उसके बाद 1978 में जो बिल पास किया गया था, उसमें यह बात जरूरी समझी गई कि बोर्ड्स को फंक्शन करना चाहिए साऊन्ड कमर्शियल प्रिंसपिल्स पर। सेक्शन 59 जो एक्ट का था, 1978 में इस मकसद से एमेंड किया गया था कि स्टेट गवर्नमेंट्स को यह बात जरूरी बताई गई कि वह सरप्लस स्पेसीफाई करें और अभी तक ऐसी बात चलती रही है और अब जो 1983 में यह बिल लाया गया है, इसमें साफ अल्फाज में यह बात कही गई है कि अब 3 परसेंट का सरप्लस स्टेट्स को दिखाना लाजमी होगा। मैं समझता हूं कि जहां तक इस बिल के बुनियादी मकसद

का सवाल है कि वह स्टेट्स को गाइडेंस दे और मुल्क में जो डिफ्रेंट स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड काम कर रहे हैं, उनको अपना कामकाज ठीक ढंग से अन्जाम देना चाहिए और कोई घांघली या फाइनेन्शियल क्राइसिस पैदा न हो और ठीक ढंग से वे काम करें, इस सबके बारे में अगर सेन्टर उनको मश्विरा देता है, तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई एतराज की बात नहीं है लेकिन जिस वक्त मरकज हमें यह मश्विरा देता है कि 3 परसेंट का सरप्लस बनाया जाना लाजमी है, तो इससे यह बात जाहिर हो जाती है कि मरकज बराहे रास्त

15.08 hrs.

[SHRI F.H. MOHSIN *in the Chair*]

बोर्ड के काम में मुदाखलत कर रहा है और मुदाखलत के माइने ये होते हैं कि मरकज कुछ अख्तियारात अपने हाथ में ले रहा है। अगरचे इस बिल में यह बात साफ नहीं है कि ये अख्तियारात कैसे उसके हाथ में हो सकते हैं लेकिन यह बात बिल्कुल साफ है कि जब इस बिल की मारफत 3 परसेंट सरप्लस लाजमी करने की बात कही गई है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जब स्टेट्स इस बात को नहीं मानेंगीं, तो फिर किसी भी सूरत में सेन्टर कोई सख्त कदम या मेजर्स लाने का अख्तियार रखता है। यह बड़ी खतरनाक बात है। हम समझते हैं कि इस तरीके से एक बहाना उसको मिल जाता है कि वह स्टेट के इस अहम इरादे में मुदाखलत कर सके और जिस स्टेट को चाहे, वह इस बहाने से रकूमात कम दे सकती है और जो उसकी फाइनेन्शियल डिफीकल्टीज हैं और खास तौर से पावर सेक्टर में, उनमें वह अड़चन डाल सकती है और मसगलः पैदा कर सकती है।

इस बिना पर मैं कहूंगा कि यह बिजली का मामला सेन्टर और स्टेट्स के ताल्लुकात को बिगाड़ने का जरिया न बने और आपस के खलफसार से कोई मकसद पूरा नहीं होगा। इस हद तक इस बिल को रहने दीजिए कि मरकज को यह अधिकार है कि वह कमीशन लगाये या मरकजी सरकार ऐसे दूसरे मेजर्स या जराये अपनाये जिनसे कि प्लानिंग कमीशन की मारफत या कोई और कमीशन बिठा कर रियासतों के कामकाज को दिखा सके और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कामकाज को दिखवा सके। लेकिन जिस वक्त आप यहां से यह पाबंदी करेंगे कि यह आपको सरपलस दिखाना है तो ठीक नहीं होगा। खुद इस बिल में यह कहा गया है कि अब तक की सारी कोशिशें वावर नहीं हुई हैं, पूरी नहीं हुई हैं, और मुल्क की किसी भी स्टेट ने मरकज के साथ इस मामले में ताऊन नहीं किया है और न मरकज को यह बताया है कि अब तक उन्होंने कितना सरपलस प्रोड्युस किया है। इसलिए इस बिना पर मैं यह अर्ज करूंगा कि यह कोई रास्ता नहीं है। बल्कि जो रियासतों के मसाईल हैं, उनके सामने जो मुश्किलात हैं उनको सेन्टर को देखना चाहिए।

पहली बात यह है कि हमारे जो थरमल प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें जो घांघलियां हैं वे इस वजह से हैं कि जो कोयला कोल माइंस से इन कारखानों को जा रहा है, वह सब ठेकेदारों के हाथ में डाल दिया गया है और इसमें उनकी मोनोपली पैदा हो रही है। जो कोयला थरमल प्रोजेक्ट्स को तक्सीम किया जा रहा है उसमें ऐश कन्टेन्ट बहुत ज्यादा है और पत्थर भी हैं। इससे इन प्रोजेक्ट्स की मशीनरी तबाह हो रही है। इस किस्म की जो मुश्किलात हैं इनकी तरफ सरकार को देखना चाहिए। इस काम में हजारों मजदूर काम कर रहे हैं। वे सब बोण्डेड लेबर हैं और उनको ठेकेदारों के रहमोकरम पर छोड़ दिया गया है। इस ओर मरकज की तवोज्जो जानी चाहिए।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे मुल्क में सोशल वेल्फेयर का सिस्टम है, हमारे यहां डेमोक्रेसी है और हम सोशलिज्म की तरफ जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को डवलप करने में हमारा बेस कमर्शियल नहीं होना चाहिये। इलेक्ट्रिसिटी को डवलप करने के

बारे में हमें यह देखना होगा कि हमारे यहां जो इसका उत्पादन होगा, वह हमारे हरेक सेक्टर के लिए एक बेसिक चीज है। एग्रीकल्चर सेक्टर, स्माल स्केल इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री सब में इलेक्ट्रिसिटी एक बुनियादी चीज है। जितना ज्यादा हम इसको पैदा करेंगे उतनी ही ज्यादा इस मुल्क की तरक्की मुमकिन होगी।

रियासत जम्मू कश्मीर से हम इनीशियल स्टेज पर दस हजार मेघावाट बिजली पूरी कन्ट्री को सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहां सूरते हाल यह है कि सर्दियों में जब पानी का बहाव कम हो जाता है, रिजरवायर्स में पानी कम हो जाता है तो हमें रियासत के बाहर से, भाखड़ा से बिजली लेनी पड़ती है। बाहर से हमें बिजली फराहम करनी पड़ती है। स्टेट गवर्नमेंट ने वक्तन-फवक्तन इशारा किया है कि अगर हमारा एक ही प्रोजेक्ट ऊरी को डवलप कर दिया जाये तो तमाम नार्दर्न इंडिया को हम बिजली दे सकते हैं। सवाल प्रोजेक्ट को आपने अपने हाथ में ले लिया है। उसके बारे में आपने पाकिस्तान की बात मानी है। सिन्ध कमीशन के तहत जो इन्टरनेशनल एग्रीमेंट उस मुल्क के साथ आपने किया है। उसके मुताबिक डेम की ऊंचाई को आपने कर दिया है जिसकी वजह से जो मकसद उस डेम का था वह पूरा नहीं हुआ है। इसमें भी सेन्टर की मर्जी है, सेन्टर की मोनोपली है। सेन्टर ने जो एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ किया है उससे स्टेट को नुकसान उठाना पड़ रहा है।

एक वहां दूरहस्ती प्रोजेक्ट है जो कि पिछले दस साल से लटक रहा है। वह पावर प्रोजेक्ट भी इतनी बिजली पैदा कर सकता है कि आप अन्दाजा नहीं कर सकते। वह जम्मू कश्मीर में तो खुशहाली पैदा करेगा ही, बल्कि जो हमारी नेबरिंग स्टेट्स हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और यू० पी० हैं उनको भी हम बिजली फराहम कर सकते हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि सेन्ट्रल सेक्टर पर ब्योरोक्रेसी का जोर है, उसका अपर हैण्ड है। हमारी जो स्कीम्स चल रही हैं और उनमें जो डिफिकल्टीज या अड़चनें पैदा हो रही हैं वे भी सब ब्योरोक्रेसी की वजह से हैं। स्टेट और सेंटर के रिलेशंस को भी इस ब्योरोक्रेसी ने तबाह करके रख दिया है और आपस में मिसअण्डर-स्टेंडिंग पैदा कर दी है। इसी की वजह से इस दूरहस्ती प्रोजेक्ट को मुकम्मिल करने में मुश्किल पेश आ रही है।

मैं जनाब यह कहना चाहता हूं कि स्टेट के अन्दर जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे उससे न सिर्फ पूरे मुल्क को फायदा पहुंचेगा बल्कि रियासत के अन्दर जो टेम्प्रेचर फ्रीजिंग प्वाइंट पर चला जाता है और जिसकी वजह से गरीब आदमी भी चोरी करने पर मजबूर हो जाता है क्योंकि उसके पास अपनी जिन्दगी को बचाने का कोई इंतजाम नहीं होता, उसकी भी हम मदद करेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा इस चीज को सेन्टर को देखना चाहिए। इसी बिना पर मैं इस बिल की बहुत सख्ती के साथ मुखालफत करता हूं और यह समझता हूं कि यह बिल एक बहाना है जिसके जरिये से सेन्टर स्टेट्स के मामलात में दखल देना चाहता है, वहां बिजली बोर्डों को डवलप करने के बहाने यह करना चाहता है। असल में उनका मकसद यह है कि स्टेट्स को प्रेशर टेक्टिकस से दबाया जाए और स्टेट्स को मोहताज बना दिया जाए।

SHRI BISHNU PRASAD (Kaliabor) : Sir, I rise to support the Bill. The amendments which has been sought to be made in the main Act, in my view, will my ensure the financial discipline and economic viability in the State Electricity Board of the country. The State Government give a lot of money to the State Electricity Boards but they have not been able to run the Boards commercially. In most of the States it has been found that Electricity Boards are running at a great loss. There is not a single State in the country where the supply of power has kept pace with the requirements. In some of the States the gap between the requirements and availability is very large. The electricity loss or transmission loss in our country is between 18 to 25 per cent while in the world it is 5 to 12 per cent. Who is responsible for loss ?

Definitely the electricity boards are responsible for the loss but they want to shift the burden on the consumer.

Sir, the Rajadhayksha Committee said :

> "The finances of the State electricity boards taken as a group, present today a dismal picture."

The criticism of some of the Opposition members that the present Bill will take away the powers of the States and at the same time they say the Government should implement the views of the Rajadhyakasha Committee. Sir, this Bill is brought just to concretise some of the views expressed by the Rajadhyaksha Committee. The question of improving the financial performance of the State Electricity Boards has been a concern of both the State Governments and the Central Government. Various committees were formed. In 1964 the Planning Commission constituted a working group which recommended that the electricity boards should earn a return of 12 per cent. Then Venkataraman Committee was formed in 1964. They also recommended that the State electricity boards should earn a return of 11 per cent. This includes, of course, the receipt of electricity duty. The gross return is 9.5 per cent excluding electricity duty. But what is the result ? As per study of 1977-78 the rate of return on average capital base is : Assam 6.8% ; Bihar 3.6% ; Gujarat 9.6% ; Orissa 2.9% ; U.P. 8.4% and so on. Only some States like Madhya Pradesh, Rajasthan and Tamil Nadu have a return of more than what was anticipated in the Venkataraman Committee. All the boards taken together the rate of return is 7.9% which is lower by about 1.6 per cent as has been anticipated in the Venkataraman Committee.

Sir, the Venkataraman Committee underlined two objectives. The first objective was to aim at higher revenue. The second objective was achieving the balance of revenue after meeting all charges, working out a net return of 3% in the capital base. The boards which have already achieved the first phase should proceed to realise the second phase. But now, Sir, the planning of the electricity in our country has to be done keeping in view that our country is the lowest in consumption compared to other countries of the world.

Sir, this can be done if we can generate more power. The entire Himalayas can produce ten times more power than what it is producing today. In this connection, I would like to mention about the Brahmaputra which is called the 'red' river. This turbulent river has to be harnessed. Then we can generate 50,000 MW of installed capacity while that of Dehang will be of the order of 20,000 MW. The Dehang project is in the upper reach of the Brahmaputra. Then it will be the highest capacity of power plant in the world and more than the total installed capacity of all the hydro-plants in India. The potential for Subansiri is assessed at 5,000 MW and 2,000 MW for Tipaimukh (Manipur—Mizoram Barak River project). These projects cannot be implemented by one State because the upper region is in Arunachal Pradesh and the lower region is in Assam.

MR. CHAIRMAN : These points are to be submitted at the time of Demands for the Ministry.

SHRI BISHNU PRASAD : Sir, these are to be taken up by the Central Electricity Board. These project can be implemented by the Centre. I would, therefore, urge upon the Government to make more funds available for implementation of these projects.

Then, Sir, in spite of having this great potentiality the per capita consumption of electricity in the North-Eastern Region in very very low. I give below the figures for each State.

Assam	...	44.91	K.W.H.
Manipur	...	6.57	,,
Meghalaya	...	46.78	,,
Nagaland	...	38.09	,,
Tripura	...	16.44	,,
Arunachal	...	18.87	,,
Mizoram	...	12.87	,,

The States like Punjab and other States have the following per capita consumption figures.

Punjab	...	303.61	K.W.H.
Haryana	...	243.89	,,
Maharashtra	...	279.60	,,

However U.P. and Bihar also are lying

far behind all India level. The per capita consumption of

Uttar Pradesh	...	89.49	,, and
Bihar	...	85.13 KW	

The all India average is 143.41 KWH.

Another point which I would like to submit is that the natural gas is Rudrasagar, Lakowa and other oil fields in Assam, is burning out. It has not been harnessed yet. This should be tapped. This will increase the generation of power in the North-Eastern Region. Therefore, I would suggest that the Centre should formulate a national policy for improving the functioning of the States Electricity Boards and the energy sector as a whole. The setting up of a National Power Grid which was agreed upon in the State Power Ministers' Conference in August, 1982, should be implemented forthwith and the whole country is to be treated as one compact unit and power should flow from surplus areas to deficit States. Unless we do it keeping in view the national perspective, it will not be possible for us to become self-sufficient in power generation.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH) : Mr. Chairman, Sir, it is difficult for me to cover all the points raised by the hon. Members during this marathan debate covering almost three days. So, I would like to refer to some of the broad points raised by the Members. But before I do so, I must express my gratefulness to the Members that they have a fairly correct appreciation of the problems that the power sector is facing, their perceptions are by and large on the right lines, and they have been greately beneficial to us in formulating our response to the present situation.

Before I refer to some of the general issues, I would like to mention just a few specific points which the hon. Members have raised. Mr. Rup Chand Pal who initiated this debate, referred to the allegations that the Centre was intruding into the powers of the States. His view was again repeated by Mr. Kabuli who went to the extreme of stating that this was a device to encroach upon the powers of States. I do not know whether he was aware of what he was opposing.

But another view also was expressed by Members who wanted us to go to the other extreme, and really to go ahead with either the take-over of the SEBs or to take upon ourselves the entire responsibility for the power sector, thus eliminating the States in one sweep. I would only like to tell Mr. Pal...

SHRI SUDHIR GIRI (Contai) : It was Mr. Satyagopal Misra who initiated the discussion, not Prof. Rup Chand Pal.

SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH : He was speaking in his sweet, sonorous Bengali. I could not catch all the implications of his speech. But certainly he thought that we were doing something to encroach upon the rights of States. He must have listened to the speeches of other Members, like the speech of Mr. S.N. Sinha.

So many Members referred to this and said that this was just a feeble attempt on our part to move in the correct direction. I would not call it a feeble attempt, but only to confirm that this amendment is hardly any attempt to intrude upon the powers of States, and the charge that there are no penalties, no sanctions against non-implementation of the minimum rate of return, as prescribed in the amending Bill may be said to be correct. I would like only to emphasize and make it clear that this is in the Concurrent List. We are working within the framework of the Constitution ; and whatever efforts we are making to improve the performance of the power sector, requires the active cooperation and a perfect rapport between the Centre and the States. I would like to tell the House that during the last few months, I have gone round nearly all the States, and had an in-depth discussion of their problems.

I am happy to inform the House that at no point of time there has been any feeling of acrimony or any feeling of dichotomy in our thinking and approach, so far as this question is concerned. It is really with this approach that the Amendment Bill has also been conceived. The amendment clearly says that there should be a minimum of 3 per cent rate of return on capital base, but we have not prescribed any penalty against the SEBs of the State Governments ; we have not prescribed any sanction against them. We are only trying to create a climate in which this achievement would certainly be made.

Members have generally referred to the losses in the Planning Commission documents. But that hardly reflects the correct financial position of the SEBs and I would refer to it later. I would like to tell the House that the situation is not as dismal or gloomy as they make it out to be. We have prescribed 3 per cent rate of interest mainly because it is just a statutory confirmation of the Venkataraman formula ; and this practice has been in vogue during the last decade. So many SEBs won't find it difficult to reach this level of functioning ; only a few might belagging behind ; they will make efforts in all directions primarily for improving the efficiency of the SEBs and would achieve this standard. We hope also that the successive Finance Commissions which adopt ; a normative standard for the functioning of the SEBs for estimating the revenue of the States will also take this into account ; and that will be a compelling factor for the SEBs to move in the right direction. So, we want to make it clear that there is no question of take over of SEBs, there is no question of taking recourse to sanction against the State Governments of the SEBs. This is a co-operative effort that we are trying to envisage in this Amendment Bill.

Reference has been made to the World Bank here. Perhaps it was not much to the point. In my speech also, I had referred to the World Bank only incidentially ; and I referred only to the extent that the World Bank also emphasised the introduction of a uniform commercial system, which is a healthy practice for any organisation to adopt. Section 59 of the existing Act refers to it and we are trying to eliminate some of the confusions or duality of interpretation because of which the cost system still continues in many of the SEBs. The Rajadyaksha Committee's Report on page 84 clearly says that accounts be presented on approval concept and not on cost basis. So, there is not much to worry about the World Bank at least while we are discussing the present Amendment Bill.

So many hon. members from Rajasthan have spoken. I feel it my responsibility to refer to some of their specific points. Even those who have not participated are very much eager to know about it like Mr. Daga, Mr. Jain and Mr. Vyas,

I would like to tell them that we have been extending substantial assistance from the Northern Grid to Rajasthan during the crucial months of February and March and we are keeping a watch over their requirements all the time, efforts are being to made to meet them. I cannot tell them the definite date to bring into operation the new thermal units also.

An hon. Member, Shri Virdhi Chander Jain, has referred to the Jaisalmare gas-based unit and I would like to tell him that a three-Megawatt unit at a cost of Rs. 2.40 crores in Jaisalmare district is yet to be approved by the C.E.A. But we are taking steps in this direction ; we are marking time and we hope that it will be cleared within two to three months and it will go a large extent. Towards meeting the requirements of this region.

There has beeen some reference to the Palana Lignite Project. We are only trying to asses the availability of lignite in that area. Based on this crucial factor there would be no reluctance on our part—in fact all efforts will be made to clear this project which will be helpful to this region again.

Shri Virdhi Chander Jain referred to the necessity or power for drinking water supply in some of the desert areas. I fully appreciate the point and I would like to request him to note that if the State Government formulates any proposal to meet this requirement, the Energy Ministry will give a most sympathetic consideration to this very important problem from a humanitarian point of view.

Shri Xavier Arakal has referred to the need for an atomic power plant for Kerala. I need not repeat it, has I have stated in this House, that the fourth atomic power plant is going to the Southern region, and all the States have staked their claims for it. We hope and wish that Karalas, claims will also be considered. A decision in this respect is going to be taken soon.

An hon. Member referred to the Kalpakkam Atomic Power Plant which tripped immediately, after, or synchronised with its inauguration by the Prime Minister. They have done very good work so far as the Kalpakkam unit is concerned,

It is a one hundred per cent indigenous project which we have been able to put up and in all such projects there is always some stabilisation period and it is likely that three to four months may lapse before it is put into full commercial operation and the benefits flow from it.

An hon. Member, Shri A.K. Roy, has referred to captive power plants and he tried to make it a little interesting by certain twists and turns. But I would like to tell him, as he may be knowing himself, that captive power plants are favourably considered by such industries which have a continuous production system. But they are not able to tolerate wide fluctuations in the supply of power. It is therefore that we are generally going ahead with this policy of approving captive power plants for such industries.

An hon. Member has referred to the needs of Tamil Nadu in respect of power. I would like to inform him that the centre is investing in the 1260 MW second stage Neyvoli Project in Tamil Nadu in addition to 600 MW in first stage. This is a super thermal power station in the sense that it is a large sized pithead station based on lignite. We are fully conscious of the fact that Tamil Nadu is short of hydel resources and its other resources are also limited. So, we are taking this into consideration and trying to sanction or approve the projects keeping this in view.

Mr. Shailani referred to the need for uniform tariff. In fact, this is one of the amendments which will come later for discussion. But it is a fact that tariff rates cannot be made uniform because the resources of the States vary. Some of the States have hydel resources which generate cheaper power. Some of them have thermal resources where the cost of producing power is higher. So, they would not like to make it average and sell power at cheaper rates. Within industries, some industries got power at cheap rates because they are power based industries and they are getting power from the HT and some others transmission and distribution system is not utilised. So, their rates are low. It is also a conscious policy of certain State Governments to encourage certain types of industries. They allow to be sold to them at cheap rates keeping in view the industrial development of the State. So it is difficult to keep tariff rates uniform.

I would like to refer briefly to the rural electrification programme. REC has a separate scheme for electrification of Harijan bastis and Tribal villages. In all new schemes this is included as a part of the scheme. We are also trying to accelerate the programme particularly in the Cangetic and Brahmaputra valley.

Now I would like to refer to some of the broad issues which have been raised by the hon. Members. Firstly, hon. Members have referred to the need for a national power grid. We have a national power programme and also a perspective plan which takes into account the requirements and the resources of power upto 2000 AD. This programme has been formulated and submitted to the Planning Commission. Our five year plans have become an integral part of the comprehensive perspective plan. So, this is the background in which we are trying to move ahead.

Historically, you will kindly recall, power generation was limited to certain towns. Then it moved to cover States and the resources of power generation are so unevenly distributed that it has become necessary to transfer power over long distances across State boundaries. The Government of India, therefore, embarked upon major programmes of setting up generating stations, both thermal and hydel at suitable locations, at coal pithead and other suitable locations. The MTPC, the NHPC the HEEPCO and the NLC are the agencies engaged in this task. For this, an integrated operation of the State system at regional level is the first in this direction. The regional operations have been integrated together and States have become an integral part of the recional system so that we can move on to the National Power Grid programme. Members are perhaps aware that only in the reeent past we have started work on the National Power Grid Development Project which involves the northern region, the southern region and the western region and we hope that this will go a long way for the evolution of the National Power Grid. This will help us in the timely investment and development of power potential in the best interest of the nation and a smooth flow of

power to all sectors of the economy. We are also trying to ensure that power from these super thermal power stations or the big hydel power stations reach the beneficiary State and we develop a transmission system adequate for this purpose. I would like, particularly, to assure the Members from Rajasthan, Punjab and other States who have raised these points and convey to them that whatever share they have in the different big projects, that will reach them according to their allocations and much more in times of certain emergencies and crisis.

Members have referred to the Rajadyaksha Committee Report and it was natural because very recently this Report and it was natural because very recently this Report has been submitted. An impression has been tried to be created that there is a system in the Government that committees are formed, reports are made available and they are put on the shelf and nothing is done about them This might be true of other reports, I cannot say, put about the Rajadayaksha Committee Report, we are very much on it, we are implementing it but I would like to tell you that two parallel lines have been taken. First is to implement such of the recommendations of the Committee which could be accepted readily regarding technical matters and such other matters where some improvement can be effected just by adopting those recommendations. The other part of the recommendations is those which involve the State Governments and where Centre-State relations are involved. This is a highly sensitive matter and we are trying to take the State Governments into confidence not only for the setting up of the Regional Electricity authority or the Central control and ownership of the EHV transmission lines and for the institutional arrangements for the selection of Chairman and the members. The total number of recommendations of the Rajadyaksha Committee is 303. Many recommendations have already been effected. Those which we can do, we are trying to adopt and implement. This is the crucial part of the Rajadyaksha Committee Report and we are trying to go into dialogues with the State Governments. This Amending Bill has not tried to impinge on the powers of the States but we have just stipulated that minimum rates of return should be prescribed and the State Governments which want to go further, can do it on their own.

Mr. Chairman, I am happy to report to the House that there are indications that the Planning Commission will allocate some more funds for the Central sector schemes. The hon. Members have referred to some J & K schemes. I would like to tell them that we are going to step up allocations for Salal scheme and the Dulhasti scheme for the Chukha transmission lines and the NTPC and the rest of the on-going projects and complete them in time so that the benefits may reach the people as soon as possible. It is likely that a further allocation of nearly Rs. 100 crores may be made available to this Ministry by the Planning Commission, realising the crucial importance that power plays in the entire economy. So, that we hope we will be able to fulfil their expectations.

Shri D.P. Yadav raised the question of the Kahalgaon project. I have specifically referred to this issue only a few days back when I stated that this project is on high priority list for 1983-84. The technical aspects which he referred to in his speech are there, but the fact is that we have cleared the Kahalgaon project. He quoted the Energy Minister, Shri P. Shiv Shankar in this connection. It is in the priority list for 1983-84, where its position has advanced a bit. We hope we shall be able to take up both the Kahalgaon scheme as well as the Chamera Project in the year 1983-84 and thus come up to the expectations of the people of the entire eastern zone, and the northern zone so far as Chamera Project is concerned.

Reference has been made to certain foreign offers for the power plants and the requirements of BHEL. We want to make it very clear that we are extremely careful that the capability of the indigenous units like BHEL should be fully exploited before we go in for acceptance of foreign offers. I am personally committed to the public sector, its enlargement, expansion and coming up to the expectations of the people. I would like to assure the House that we would take all care to see that the capacity which is there in BHEL is fully utilized.

I have referred to the fact that the

primary limitation on us is the constraint of resources. Our target for the Sixth Plan was 19,666 MW. In spite of the present constraints, we hope we will be able to reach a figure of close to 15,000 MW, which is an achievement by itself.

A suggestion has been made in an editorial in the press today that BHEL should extend credit to SEB and that it should get export credit from so some of the foreign countries. This is not a very workable proposition, because the hardware equipment forms only 30 to 35 per cent of our total requirements in thermal projects and less than 30 per cent in hydel projects. So, even if we get the equipment from abroad, we have to find rupee resources to meet the other requirements like civil works, colony and other things. So, it is one of the areas where we are facing difficulties. It is in this background that the Minister made a statement that we shall accept foreign offers for limited purposes in a highly selective manner so that our power generation programme can keep pace with the requirements of the country.

Now I would like to refer to one point before I conclude my speech. That is a very crucial point. A reference has been made to the suggestion that the private sector can be entrusted with power generation.

MR. CHAIRMAN : You may be brief that we finish the consideration stage of this Bill at least.

SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH : Yes. I would only like to tell you that I have already repeated all this that we are guided by the Industrial Policy Resolution of 1956 enunciated by Pandit Jawaharlal Nehru. We are still committed to the socialistic pattern of society envisaged in the Industrial Policy Resolution and I would like to tell you that in the Industrial Policy Resolution *(Interruptions)*.

15.58 Hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

I would like to tell you firstly what is the basis for such a suggestion. A general impression has been created that the public sector undertakings are functioning inefficiently and efficiency is the monopoly of the private sector. But this charge with all the emphasis at my command – and I will prove by facts and figures that the public sector undertakings are functioning at least as efficiently, or much better than some of the private undertakings.

Sir, a reference was made to the Tatas. There are four undertakings – the Tatas, the Ahmedabad Electric Supply Company, the Calcutta Electric Supply Company and the Renusagar Power Company. *(Interruptions)*. About Trombay, I would like to tell you, the Trombay power station is based on oil and gas and a comparison can be made only for power projects based on oil and gas and I would like to tell you that its performance can be compared to our public sector undertakings, Dhuvaran of the GEB, which also burns oil, and it is as good as the Trombay's. So, again the Calcutta Electric Supply Company and the Ahmedabad Electric Supply Company get uniform and good quality coal because they have old boilers and there are public sector undertakings like NLC which have a higher PLF than the Ahmedabad or Calcutta Electric Supply Companies which also get uniform and good quality coal. So, comparisons can be made in a comparable situation, you cannot compare an oil based power project with a coal based power project and I would like to make it clear that our performance has been equally good at least, if not better.

Then, about the constraint of resources I would like to tell you that all the proposals which the private sector has made are always based on institutional finance. They would like to avail of the kitty which we already have with the financial institutions and plan a power project of their own. I have always stated in this House that if they can come up in a substantial measure with their own resources, with their own support, then it can certainly be considered, but if they want to share the kitty already available with us, I do not find any point in it and we have received the proposal for the kitty. There are many snags in it.

15 59 Hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

I do not want to discuss this here, but I would only like to tell the House that it is

under our examination, but no impression should be created, and I am fully confident that the public sector undertakings have achieved and are capable of achieving a higher efficiency than some of the private sector undertakings. Just on the ground of

16.00 Hrs.

efficiency there is absolutely no justification for private sector entering into power generation. This is a matter of faith in the public sector for our party ..

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur): That means you are not going to set up thermal power station by the private sector. Is it not ?

SHRI CHANDRA SHEKAR SINGH : I have said what I have said.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER : You are not going to enter the private sector so as to setup thermal power station in our country.

SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH : I have made it clear. There cannot be any answer 'yes' or 'no'. I have made it very clear that I do not consider and facts are not so that efficiency is the monopoly of the private sector. But if they come up with any proposal which is backed by substantial resources of their own, then it can be considered. We have not received any such proposal and therefore, we do not see ..

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South) : This will be deviation from Nehru policy.

SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH : I do not see any ground for deviation from Industrial Policy Resolution of Pandit Jawaharlal Nehru and we shall see that power sector progresses on right lines.

I hope I have tried to cover nearly all the points raised by the hon. Members and hope that they would approve motion for consideration of the Bill.

MR. SPEAKER : The question is :

"That the Bill further to amend the Electricity (Supply) Act, 1948, be taken into consideration."

The motion was adopted.

16.02 Hrs.

DISCUSSION ON STATEMENT OF MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS *RE* HIS RECENT VISI TO SRI LANKA

MR. SPEAKER : Hon. Members, we have to take up discussion on the statement made by the Minister of External Affairs in the House on 2nd August, 1983, regarding his recent visit to Shri Lanka.

Before we start, I may make it clear that as expressed earlier during the day and also in my discussions, I think we shall split it into two days. Tomorrow important events might be coming up. So, we shall discuss it upto 6 O'Clock to-day and also take it up at 6 O'clock tomorrow.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur) : Why not upto 15.30 tomorrow ?

MR. SPEAKER : No. Other work has also to be done.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South) : How have you taken the decision ? This was not discussed in the Business Advisory Committee.

MR. SPEAKER : This was not discussed in the Business Advisory Committee.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : Do you want the House to decide it ?

MR. SPEAKER : Yes. This is what I have discussed.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : Why this deviation ?

MR. SPEAKER : It is deviation for the benefit of the House so that they may get more time. More-over, more important things are coming up. I may take the House into confidence that there are certain important things in the offing and it might have repercussions so that we take them into consideration and then tomorrow we shall finish it. Otherwise, there is no harm and no bar if you take it all today.

SHRI C. T. DHANDAPANI (Pollachi) : We are discussing it in the evening today. We may take it up at 12 O'clock tomorrow and complete it by 15.30.